III. TECHNO-ECONOMICALLY EXAMINED BY CENTRAL WATER COMMISSION AND CONSIDERATION DEFERRED BY ADVISORY COMMITTEE DUE TO NON-CLEARANCE OF THE PROJECT FROM ENVIRONMENTAL AND FOREST ANGLE.

	Major			
1.	Dudhganga	154.73	81.97	9/83
	Medium			
	—	—	—	

IV. THE STATE HAS TO SORT OUT VARIOUS TECHNO ECONOMIC ISSUES & OBTAIN ENVIRONMENT/FOREST/REHABILITATION & RESETTLEMENT CLEARANCES AS APPLICABLE.

	Major			
1.	Human	168.15	59.99	9/91
2.	Tultuli	82.64	30.59	11/90
	Medium			
1.	Saiki-Makardhokra	12.20	5.028	8/91
2.	Bor-Dahegaon	7.50	1.795	3/90
3.	Tajanapur Lift Irrigation	9.78	2.74	1/93
4.	Kordinal	10.36	2.61	1/93
5.	Dara	13.82	2.299	1/93
6.	Lower Panzara (Akkalpada)	48.98	6.19	1/90
7.	Nagan	19.47	2.49	1/93
8.	Brahmangaon Lift	8.73	3.20	2/93
9.	Chandrabhaga	24.79	5.61	2/93
10.	Pentakli Tank	20.72	10.49	12/92

NOTE : The clearance of the project depends upon how soon the State Government complies with the observations of the Central Appraising Agencies and obtains clearances from the Ministry of Environment & Forests from environment and forest angle and from Ministry of Welfare if displacement of Scheduled Castes and Scheduled Tribes population is there.

बिहार में औरंगाबाद सिंचाई परियोजना

2415. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में पटना में यह घोषणा की है कि बिहार में प्रस्तावित औरंगाबाद सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना का कार्य कब से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है और उस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(ग) उपर्युक्त परियोजना से किन-किन क्षेत्रों के कितने क्षेत्र-भाग में सिंचाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा यह स्कीम मूल रूप से 125.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुछ टिप्पणियों के साथ 1983 में अनुमोदित की गयी थी । राज्य सरकार से 297.81 करोड़ रुपये (87-88 के मूल्य स्तर पर) का संशोधित अनुमान जुलाई, 1989 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुआ था । केन्द्रीय जल आयोग ने हाल ही में इस परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा किया है । धन की कमी के कारण केवल प्रारंभिक कार्य ही किये गये हैं । इस स्कीम पर 3/93 तक लगभग 15.51 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है । इस परियोजना के लिये आठवीं योजना के वास्ते 20 करोड़ रुपये के परिव्यय तथा 1993-94 के लिये 5 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) इस परियोजना का कृष्य कमान क्षेत्र पलामू जिले में 63,330 हेक्टेयर तथा औरंगाबाद जिले में 1,870 हेक्टेयर है ।

राज्यों के बीच पानी का बंटवारा

2416. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के लिए कोई ठोस उपाय किया है;